आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

सत्यमेव जयते

साप्ताहिक सूचना पत्र

दिनांक 9.10.2026 से 15.10.2026

छठा संस्करण

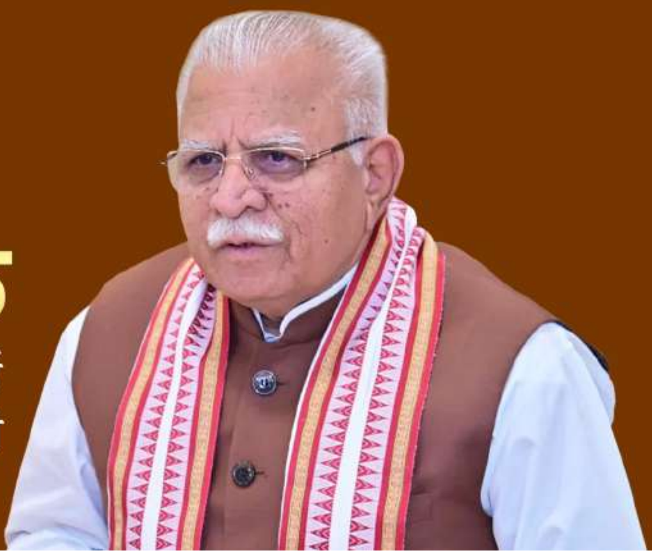

श्री मनोहर लाल

माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य
तथा विद्युत मंत्री

सप्ताह की प्रमुख उपलब्धियाँ

1. HUDCO ने लाभांश में बनाया नया रिकॉर्ड, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को सौंपा ₹908.36 करोड़ का चेक
2. कचरे से संसाधन की ओर: MoHUA परिसर में एरोबिन स्थापित
3. चेक गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल का DMRC दौरा, प्रौद्योगिकी साझेदारी पर विचार-विमर्श
4. NBCC के नाम तीन सम्मान, सतत विकास और जनकल्याण के प्रयासों को मिली पहचान
5. CITIIS 2.0: Apex Committee Meeting में सर्कुलर इकोनॉमी और एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन को बढ़ावा

15 अक्टूबर, 2026

HUDCO ने लाभांश में बनाया नया रिकॉर्ड, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को सौंपा ₹908.36 करोड़ का चेक

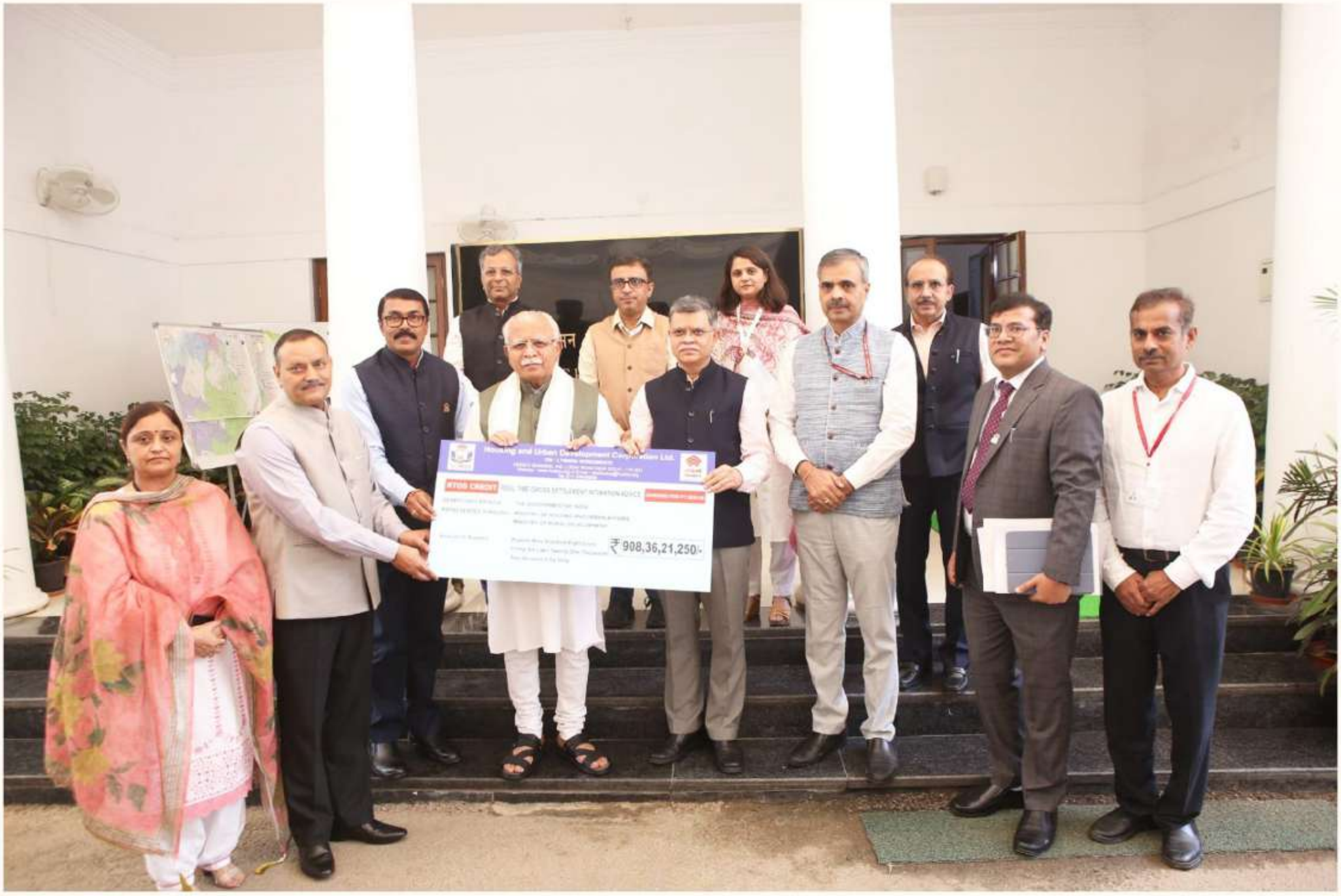

HUDCO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹908.36 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक लाभांश घोषित कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। HUDCO के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजय कुलश्रेष्ठ ने यह लाभांश माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल को प्रदान किया। इस अवसर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के शहरी विकास विभाग के सचिव श्री सतेंद्र सिंह तथा HUDCO के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

यह रिकॉर्ड लाभांश HUDCO के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, परिचालनगत सुदृढ़ता और देश के शहरी विकास में उसके निरंतर योगदान को दर्शाता है। भारत के शहरी परिदृश्य को रूपांतरित करने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, HUDCO अर्बन इन्वेस्ट विंडो (UiWIN) और भारत सरकार की अर्बन चैलेंज फंड (UCF) जैसी नवोन्मेषी पहलों को आगे बढ़ा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य शहरी अवसंरचना को सशक्त बनाना, सतत विकास को प्रोत्साहित करना तथा भविष्य के लिए समावेशी, सुदृढ़ और जीवंत शहरों के निर्माण को बढ़ावा देना है।

12 अक्टूबर, 2026

कचरे से संसाधन की ओर: MoHUA परिसर में एरोबिन स्थापित

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) तथा IPCA के सहयोग से नई दिल्ली स्थित संकल्प भवन के कार्यालय परिसर में एरोबिन स्थापित किए हैं। यह इन-सिटू गीला कचरा प्रबंधन सुविधा स्वच्छता प्रबंधन नियम, 2026 के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

कार्यालय परिसर में उत्पन्न होने वाले रसोई के गीले कचरे को अब इन एरोबिन में एकत्रित कर संसाधित किया जाएगा। इस प्रक्रिया में कचरा प्राकृतिक रूप से विघटित होकर पोषक-समृद्ध खाद में परिवर्तित होगा। तैयार खाद का उपयोग कार्यालय के उद्यानों और हरित क्षेत्रों में किया जाएगा, जिससे कचरे को उपयोगी संसाधन में बदलने का एक बंद चक्र स्थापित होगा।

इस पहल के तहत IPCA की टीम ने कार्यालय कर्मचारियों को एरोबिन के सही उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया। कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया कि रसोई के गीले कचरे को एरोबिन में डालने से वह किस प्रकार खाद में परिवर्तित होता है।

12 अक्टूबर, 2026

चेक गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल का DMRC दौरा, प्रौद्योगिकी साझेदारी पर विचार विमर्श

रेलवे, मोबिलिटी और विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्रों के प्रतिनिधियों वाले चेक गणराज्य के एक बहु-क्षेत्रीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली मेट्रो भवन स्थित चालक-रहित (ड्राइवरलेस) संचालन नियंत्रण केंद्र (Operations Control Centre) का दौरा किया।

प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार, दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के CEO श्री संजय जमुआर तथा DMRC के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग, प्रौद्योगिकी साझेदारी, निवेश और व्यावसायिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
Delhi Metro Rail Corporation Limited

9, 10, 15 अक्टूबर, 2026

NBCC के नाम तीन सम्मान, सतत विकास और जनकल्याण के प्रयासों को मिली पहचान

NBCC (India) Limited को सार्वजनिक क्षेत्र में उत्कृष्टता, राष्ट्र-निर्माण, सतत एवं हरित अवसंरचना विकास और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के क्षेत्र में योगदान के लिए तीन प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान कंपनी की अवसंरचना विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

10 अक्टूबर 2026 को NBCC को राष्ट्र-निर्माण में योगदान और सार्वजनिक क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए PHDCCI Public Sector Excellence and Nation-Building Award प्रदान किया गया। NBCC के कार्यपालक निदेशक (मा.सं.प्र.) श्री के. गणेशिया ने संगठन की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया और इसे NBCC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) डॉ. के. पी. महादेवास्वामी को प्रदान किया।

इसके अतिरिक्त, NBCC को संधारणीय, स्वच्छ एवं हरित अवसंरचना निर्माण के क्षेत्र में भारत के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक उद्यम की श्रेणी में 11वें अटल शास्त्र मार्केनॉमी पुरस्कार 2026 का विजेता घोषित किया गया। 9 अक्टूबर 2026 को मुंबई स्थित वालचंद हीराचंद हॉल, IMC Chamber of Commerce and Industry, चर्चगेट में आयोजित समारोह में NBCC की ओर से उप महाप्रबंधक (इंजी.) श्री विवेक पटेल ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

वहीं, चौथे फॉर्च्यून लीडरशिप अवॉर्ड्स 2026 में NBCC को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सामुदायिक कल्याण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता बेहतर बनाने के प्रति कंपनी के प्रयासों को मान्यता देता है। NBCC की ओर से उप महाप्रबंधक (मा.सं.प्र.) श्री फर्डिनेंड सोरेंग ने पुरस्कार प्राप्त किया, जिसे बाद में महाप्रबंधक (मा.सं.प्र.) सुश्री मंजीता महाजन श्रीवास्तव ने डॉ. के. पी. महादेवास्वामी को प्रदान किया।

ये तीनों सम्मान NBCC के सार्वजनिक क्षेत्र में योगदान, पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी अवसंरचना विकास तथा स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता, वंचित समुदायों के सहयोग और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों को रेखांकित करते हैं।

12 अक्टूबर, 2026

CITIIS 2.0: Apex Committee Meeting में सर्कुलर इकोनॉमी और एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन को बढ़ावा

CITIIS कार्यक्रम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), French Development Agency (AFD), German Development Bank (KfW), European Union तथा National Institute of Urban Affairs (NIUA) की संयुक्त पहल है। इसके दूसरे चरण, CITIIS 2.0 के अंतर्गत सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों पर आधारित 18 सतत अवसंरचना परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन परियोजनाओं का मुख्य फोकस Integrated Solid Waste Management है। इसके साथ ही, यह कार्यक्रम राज्यों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित पहलों को भी समर्थन प्रदान करता है।

12 अक्टूबर 2026 को CITIIS 2.0 टीम ने नई दिल्ली स्थित संकल्प भवन में पाँचवीं Apex Committee Meeting आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता MoHUA के सचिव श्री सतेंद्र सिंह, IAS ने की। Apex Committee ने कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की और CITIIS 2.0 की गतिविधियों के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए प्राथमिकताओं तथा प्रमुख निर्णयों पर रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया। बैठक में संयुक्त निदेशक (SBM), NIUA के निदेशक तथा AFD, KfW, European Union और NIUA के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

सत्यमेव जयते

इस सप्ताह के प्रमुख समाचार

द पायनियर
(10 अक्टूबर, 2026)

बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो विस्तार की व्यवहार्यता रिपोर्ट मंजूर

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परियोजना की अंतिम व्यवहार्यता रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इसके बाद परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेज दी गई है। इससे फरीदाबाद और पलवल क्षेत्र में मेट्रो संपर्क बढ़ाने की योजना आगे बढ़ी है। यह जानकारी मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 66वीं बोर्ड बैठक में दी गई। बैठक में राज्य की विभिन्न मेट्रो और नमो भारत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान गुरुग्राम रैपिड मेट्रो में 88.81 लाख यात्रियों ने सफर किया,

- परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट केंद्र को भेजी, मेट्रो विस्तार से पलवल तक कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद

जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 79.57 लाख थी। इस तरह यात्रियों की संख्या में 11.62 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि में परिचालन से होने वाली आय भी 16.66 करोड़ रुपये से बढ़कर 18.60 करोड़ रुपये हो गई। गैर-किराया राजस्व में 64.34 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। मेट्रो स्टेशनों पर लाइसेंस पर दिए गए स्थानों से किराये की आय 2.82 करोड़ रुपये से बढ़कर 3.50 करोड़ रुपये हो गई। वहीं, विज्ञापन अधिकारों की ई-नीलामी से 23.14 करोड़ रुपये की आय हुई, जबकि पिछले वर्ष यह 13.39 करोड़ रुपये थी। बैठक में 136.30 किलोमीटर लंबे दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत कॉरिडोर पर भी चर्चा हुई। इसकी अनुमानित लागत 33,051.15 करोड़ रुपये है और इसमें 17 स्टेशन प्रस्तावित हैं। भविष्य में चार अतिरिक्त स्टेशन बनाने का प्रावधान भी रखा गया है। इसके अलावा गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा-ग्रेटर नोएडा नमो भारत कॉरिडोर का प्रस्ताव विचाराधीन है। गुरुग्राम और फरीदाबाद क्षेत्र में मार्ग तथा स्टेशनों का निर्धारण राज्य स्तर पर किया जा चुका है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संबंधित विभागों और विकास प्राधिकरणों को सुझावों के लिए भेजी गई है। सेक्टर-56, गुरुग्राम से पंचगांव तक 35.25 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर में 28 स्टेशन बनाए जाने हैं। यह कॉरिडोर पंचगांव में नमो भारत मार्ग से जुड़ेगा। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

द पायनियर
(12 अक्टूबर, 2026)

मोदी ने चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण का किया उद्घाटन

एजेंसी। चेन्नई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के तहत लगभग 4,900 करोड़ रुपये की लागत से बने पूनामल्ली-वडापलानी खंड का उद्घाटन किया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के साथ मेट्रो ट्रेन में सवारी की। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री विजय ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की मौजूदगी में नई मेट्रो सेवाओं को हरी झंडी दिखाई और ट्रेन में सफर किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने टिकट खरीदा और टिकट काउंटर पर तैनात कर्मचारी से संक्षिप्त बातचीत भी की। ये नई मेट्रो सेवाएं मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के कॉरिडोर-चार के तहत संचालित होंगी। लगभग 15 किलोमीटर के नवनिर्मित खंड में कुल 11 एलिवेटेड स्टेशन हैं। इस नए कॉरिडोर पर 3.7 किलोमीटर लंबा एक अनोखा डबल-डेकर ढांचा तैयार किया गया है। इसमें चालक के बिना मेट्रो ट्रेनें चलाने के लिए आधुनिक सिग्नल प्रणाली भी लगाई गई है। इस नए कॉरिडोर के शुरू होने से यात्रियों के सफर का समय कम होगा और तेजी से विकसित हो रहे पश्चिमी उपनगरों से चेन्नई के मुख्य हिस्से में आना-जाना आसान होगा।

पीएमी मोदी ने मुख्यमंत्री विजय संग मेट्रो में किया सफर

हरिभूमि
(12 अक्टूबर, 2026)

करीब 6 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान

गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट पर अगले हफ्ते मुहर संभव

हरिभूमि न्यूज ▶▶ [illegible]

गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर परियोजना पर अगले सप्ताह अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। इसे लेकर दिल्ली और गुरुग्राम की संयुक्त टीम ने फरीदाबाद में प्रस्तावित रूट का निरीक्षण किया। टीम ने बिजली की हाईटेंशन लाइन, टावर, सब स्टेशन और पेयजल पाइपलाइन समेत अन्य तकनीकी बाधाओं का जायजा लिया। इन्हें शिफ्ट करने पर सहमति बनी है। इस काम पर करीब छह करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

हरियाणा और केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद परियोजना की तैयारियां तेज हो गई हैं। पांच सदस्यीय टीम ने गुरुग्राम रोड से सैनिक कॉलोनी, बाटा चौक और ग्रेटर फरीदाबाद तक प्रस्तावित रूट का निरीक्षण किया। टीम में आरआरटीएस के डिप्टी चीफ इंजीनियर प्रदीप यादव, कंसल्टेंट, एचएसवीपी के एसडीओ और जेई तथा एफएमडीए के कार्यकारी अभियंता केएस पठानिया शामिल रहे।

निरीक्षण में तीन स्थानों पर 66 केवी बिजली लाइनें परियोजना के रास्ते में बाधा बनती मिलीं। इन्हें शिफ्ट करने के साथ बिजली के टावर भी हटाए जाएंगे। वहीं, सेक्टर-28 और 29 के कट पर आ रही पेयजल पाइपलाइन को भी दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा।

> नमो भारत ट्रेन का इंतजार कर रहे फरीदाबाद वासियों के लिए अच्छी खबर है। गुरुग्राम-फरीदाबाद और नोएडा आरआरटीएस प्रोजेक्ट को जल्द फाइनल मुहर लगने जा रही है। इस रूट पर नमो भारत ट्रेन चलने से एनसीआर के तीन बड़े शहर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे।

66 केवी बिजली लाइनें परियोजना के रास्ते में बाधा बनती दिखाई दीं

एक ही ट्रैक पर दौड़ेंगी दो तरह की ट्रेन

परियोजना में फरीदाबाद में लगभग 16 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर प्रस्तावित है। सैनिक कॉलोनी, एनआईटी, बाटा चौक और सेक्टर-87/88 चौक प्रमुख स्टेशन होंगे। कॉरिडोर गुरुग्राम से फरीदाबाद होते हुए नोएडा की ओर जाएगा। इसकी खासियत यह है कि एक ही ट्रैक पर नमो भारत और लोकल मेट्रो ट्रेनें चल सकेंगी।

गुरुग्राम मोड़ पर फ्लाईओवर की भी जांच

टीम ने गुरुग्राम मोड़ पर आरआरटीएस और ईस्ट-वेस्ट परियोजना के प्रस्तावित एलिवेटेड फ्लाईओवर का भी निरीक्षण किया। इसका उद्देश्य दोनों परियोजनाओं के निर्माण और आपसी तालमेल में आने वाली तकनीकी अड़चनों को दूर करना है। अगले सप्ताह मंत्रालय में होने वाली बैठक में परियोजना के प्रस्तावों पर चर्चा की उम्मीद है।

सत्यमेव जयते

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

इस सप्ताह के प्रमुख समाचार

राजस्थान पत्रिका
(12 अक्टूबर, 2026)

ई-बसों की राह आसान : चार निगम और चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड में हुआ समझौता

240 ई-बसों की कैमरों से होगी निगरानी, टिकट ऑनलाइन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रायपुर. छत्तीसगढ़ में 240 ई-बसों के संचालन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। इसके लिए नवरात्र के पहले दिन रविवार को डिप्टी सीएम अरुण साव की मौजूदगी में चारों नगर निगमों और चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के बीच कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही बसों के रंग और कट-आउट का भी विमोचन हुआ। बस केसरिया रंग की होगी। इन ई-बसों की खास बात यह होगी कि इसमें सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम होंगे। हर बस में छह कैमरे लगे होंगे। मोबाइल ऐप के जरिए बसों की लोकेशन मिलेगी और यात्री ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं। ई-बसों के संचालन से शहरी परिवहन में आरामदायक, किफायती और प्रदूषणमुक्त सफर की शुरुआत होगी। इन सभी ई-बसों का संचालन कब से शुरू होगा यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन विभाग नवंबर में बिलासपुर और भिलाई में 20-20 ई-बसों का संचालन प्रारंभ करने की तैयारी में है।

सभी काम समय सीमा में पूरा करने पर जोर: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कार्यक्रम में योजना के उद्देश्यों और संचालन की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहरों में बढ़ती आबादी और परिवहन की जरूरतों को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन का आधुनिकीकरण आवश्यक है। योजना की सफलता के लिए चार्जिंग व्यवस्था, डिपो, बस-स्टॉप और रखरखाव केंद्र सहित आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास, विभागीय समन्वय और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करना जरूरी है। इस दौरान विभाग के संचालक नीलेश महादेव क्षीरसागर, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल और चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पंकज गांधी, रायपुर महापौर मीनल चौबे, बिलासपुर महापौर पूजा विधानी, कोरबा महापौर संजू देवी राजपूत, दुर्ग महापौर अलका बाघमार और [illegible] महापौर [illegible] देवांगन मौजूद थे।

इन शहरों में इतनी बसें

100 रायपुर में
50 दुर्ग-भिलाई में
50 बिलासपुर में
40 कोरबा में

आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल

डिप्टी सीएम साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा स्वच्छ, हरित और विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। बढ़ते शहरीकरण के साथ यातायात, वायु प्रदूषण और ईंधन की खपत जैसी चुनौतियां बढ़ रही हैं। इलेक्ट्रिक बसों से ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी, पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता और ध्वनि प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।

रूट चार्ट पर फोकस

एग्रीमेंट होने के बाद सरकार का फोकस ई-बसों के रूट चार्ट पर होगा। इसके लिए डिप्टी सीएम साव ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, व्यावसायिक स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों तक सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराना जरूरी है।

राजस्थान पत्रिका
(12 अक्टूबर, 2026)

पिंक पहल : कचरा प्रबंधन से महिला सशक्तीकरण तक

जहां कचरा था, वहां महिलाओं ने निकाल लिया रोजगार का रास्ता

पटना में कचरे को रोजगार, स्वच्छता और पर्यावरण से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहां पिंक मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) में महिलाएं कचरा प्रबंधन की कमान संभाल रही हैं। इसमें पुराने-बेकार वाहनों को मोबाइल पिंक टॉयलेट बनाया गया है। यानी एक ओर महिलाओं को काम का अवसर मिल रहा है, दूसरी ओर कचरे और कबाड़ को उपयोगी संसाधन में बदलने की कोशिश हो रही है। इसमें मुख्य रूप से महिलाएं काम रही हैं। महिला सुपरवाइजर के नेतृत्व में सूखे और गीले कचरे के प्रबंधन की प्रक्रिया पूरी हो रही है।

इस तरह हुई शुरुआत

पिंक एमआरएफ शुरू करने के पीछे एक प्रमुख उद्देश्य कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम के अवसर तैयार करना था। परियोजना टीम ने इस विचार के साथ पटना नगर निगम से संपर्क किया। नगर निगम के सहयोग से ऐसा संभव हुआ। पिंक एमआरएफ और मोबाइल पिंक टॉयलेट की ये पहल सफाई व्यवस्था तक सीमित नहीं है। इसके जरिए महिलाओं के लिए रोजगार, कचरा प्रबंधन, पुराने संसाधनों के दोबारा इस्तेमाल और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को एक साथ जोड़ा गया है।

दैनिक भास्कर
(14 अक्टूबर, 2026)

भास्कर एक्सक्लूसिव दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत कॉरिडोर का काम तेज

दिल्ली से मुरथल-पानीपत-करनाल के लिए हर 6 से 19 मिनट में मिलेगी नमो भारत ट्रेन, 242 फेरों के साथ वर्ष 2031 से चलेगी

सुभाष राव | पानीपत

दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत कॉरिडोर 2031 तक तैयार करने की तैयारी है। इसे लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने काम तेज कर दिया है। मिट्टी की सैंपलिंग के बाद सिविल, आर्किटेक्चरल और इलेक्ट्रिकल कार्यों की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए डिटेल्ड डिजाइन कंसल्टेंट नियुक्त किया जा रहा है। इसके लिए टेंडर लगाया गया है। एनसीआरटीसी ने इस रूट पर साल 2054 तक की यात्री मांग को ध्यान में रखते हुए प्लान तैयार किया है। इसके अनुसार, ट्रेनों के फेरों के लिए पूरे रूट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। शुरुआत में इन रूटों पर कुल 242 फेरे लगेंगे। इसमें दिल्ली के सराय काले खां से सोनीपत के मुरथल तक हर 6.34 मिनट में ट्रेन उपलब्ध होगी। रोजाना 121 फेरे लगेंगे। मुरथल से पानीपत के गांजबड़ तक हर 9.51 मिनट में ट्रेन चलेगी। रोज 81 फेरे होंगे। गांजबड़ से करनाल तक हर 19.02 मिनट में ट्रेन मिलेगी। इस रूट पर रोजाना 40 फेरे लगेंगे। 2054 तक ट्रेनों के कुल फेरे बढ़कर 450 हो जाएंगे। इससे ट्रेनों के बीच समय का अंतराल कम होगा। 6 कोच की नमो भारत ट्रेन में 1928 यात्री सफर कर सकेंगे। दिल्ली से करनाल तक सड़क मार्ग से 3 घंटे लगते हैं। नमो भारत ट्रेन से यह सफर डेढ़ घंटे (90 मिनट) में पूरा हो सकता है।

मुरथल और गांजबड़ में मेंटेनेंस डिपो इस तरह के बनेंगे।

दिल्ली-मेरठ रूट तक जाएंगी ट्रेनें, स्पीड 160 तक: पानीपत-दिल्ली कॉरिडोर सीधे दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर से इंटरकनेक्ट होगा। इससे पानीपत व करनाल के यात्री नमो भारत ट्रेन में मेरठ तक का सफर कर सकेंगे। ट्रैक पर अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वैसे एलिवेटेड सेक्शन पर ट्रेन 160 किमी प्रति घंटा व अंडरग्राउंड हिस्से में 140 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी।

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
सत्यमेव जयते

इस सप्ताह के प्रमुख समाचार

राजस्थान पत्रिका
(12 अक्टूबर, 2026)

सड़कों की सफाई व्यवस्था होगी मजबूत

धूल प्रदूषण से निपटने को 12 मल्टी-पर्पज वाहन उतारे

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

धूल प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़कों की सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने 12 नए मल्टी-पर्पज वाहन उतारे हैं। महापौर प्रवेश वाही ने मंगलवार को सिविक सेंटर से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर वाहन में 7 हजार लीटर पानी की टंकी है।

महापौर वाही ने कहा, ये वाहन धूल के कणों को नियंत्रित करने, सड़कों को स्वच्छ रखने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयासों को मजबूती देंगे। वाहनों में एंटी-स्मॉग गन, वाटर स्प्रिंकलर, जेटिंग सिस्टम और वॉशिंग गन लगाई गई हैं। इनसे सड़कों पर पानी का छिड़काव और धुलाई करने के साथ छोटी ढकी नालियों व पुलियों की रुकावटें दूर की जा सकेंगी। सार्वजनिक शौचालयों की सफाई में भी इनका इस्तेमाल होगा।

एमसीडी के मुताबिक, प्रत्येक वाहन की लागत 35.06 लाख रुपए है और अनुमानित उपयोगी जीवन 15 साल रखा गया है। संचालन और रखरखाव के लिए ओएंडएम मॉडल अपनाया जाएगा। गुणवत्ता जांच के लिए तृतीय-पक्ष निरीक्षण और आईआईटी-दिल्ली के माध्यम से जांच की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि, प्रदूषण पर वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि इन्हें किन इलाकों में, कितनी नियमितता से और किस निगरानी व्यवस्था के तहत चलाया जाता है।

राजस्थान पत्रिका
(11 अक्टूबर, 2026)

आज होगा अनुबंध: 4 बड़े शहरों में जल्द दौड़ेंगी ई-बसें

रायपुर में 100, बिलासपुर व दुर्ग-भिलाई में 50-50, कोरबा में दौड़ेंगी 40 ई-बसें

पत्रिका ब्यूरो

[illegible]

कहां कितनी बसें	
रायपुर	100
बिलासपुर	50
दुर्ग-भिलाई	50
कोरबा	40

ऑपरेटर कंपनी और अर्बन सोसाइटी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर आज

किराए-संचालन की व्यवस्था

[illegible]

कंपनी ने बैंक गारंटी जमा कर दी...

[illegible]

[illegible]

-अनुपम तिवारी,
नोडल अधिकारी,
ई-बस सेवा

अमर उजाला
(12 अक्टूबर, 2026)

नमो भारत से पार्सल पहुंचाने की संभावनाएं तलाशेगा एनसीआरटीसी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के जरिये पार्सल परिवहन की संभावनाएं तलाशने के लिए ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य नमो भारत के बुनियादी ढांचे का बेहतर इस्तेमाल कर एनसीआर में सामान पहुंचाने की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक और टिकाऊ बनाना है। समझौते के तहत नमो भारत सेवाओं को ब्लू डार्ट के मौजूदा पार्सल पिकअप और डिलीवरी नेटवर्क से जोड़ने की संभावनाओं पर काम किया जाएगा। इससे पार्सल की आवाजाही के लिए एक वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिल सकती है। इस पहल में शहरी क्षेत्रों में सामान की तेज और व्यवस्थित आवाजाही के लिए नमो भारत के बुनियादी ढांचे के उपयोग पर विचार होगा। इससे पार्सल परिवहन के मौजूदा साधनों पर दबाव कम करने और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के अवसर तलाशे जाएंगे।

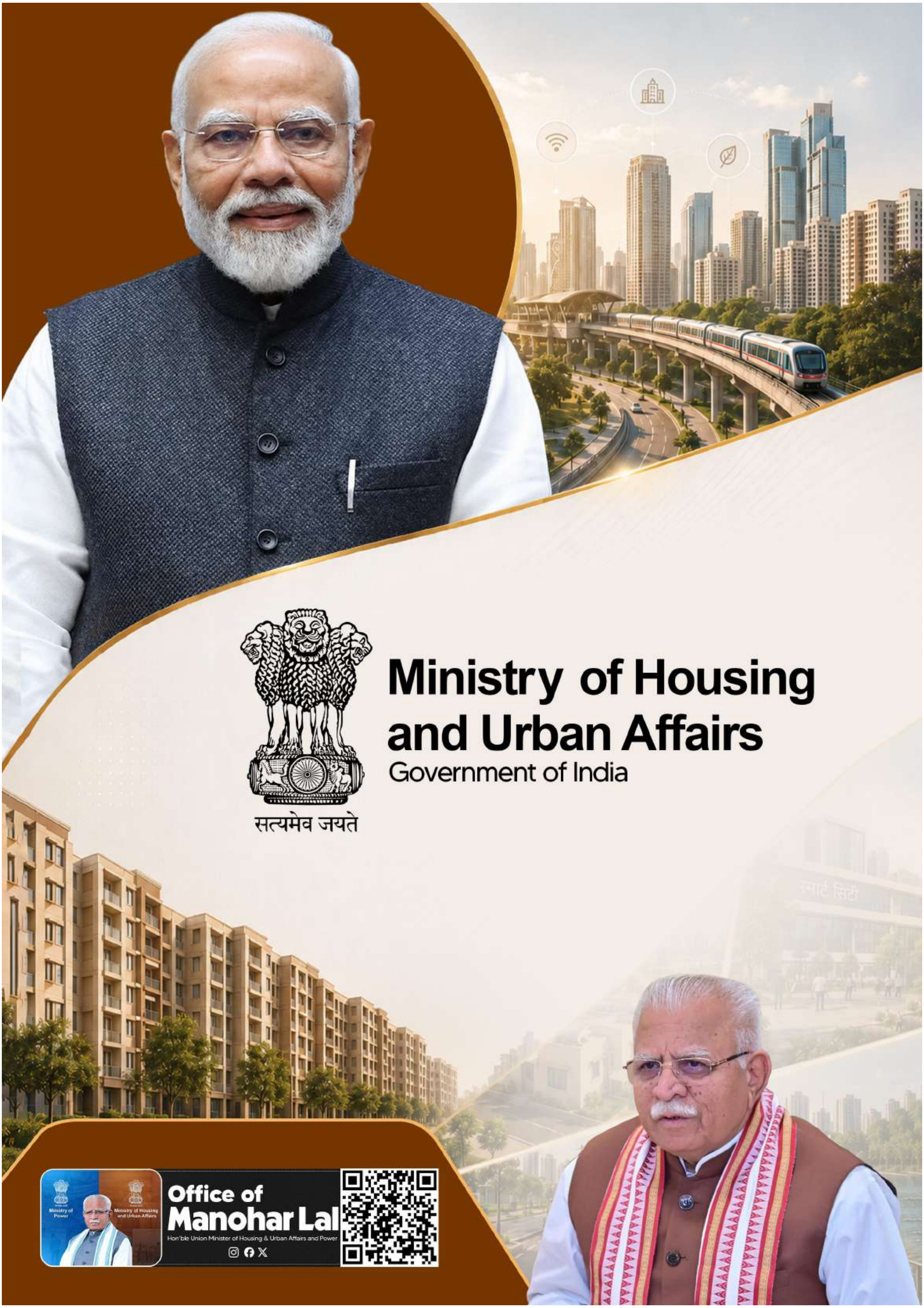
Ministry of Housing
and Urban Affairs
Government of India
सत्यमेव जयते
Ministry of Power
Ministry of Housing and Urban Affairs
Office of
Manohar Lal
Hon'ble Union Minister of Housing & Urban Affairs and Power